



2026:AHC:57750

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9479 / 2026

शमशाद

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राकेश चन्द्र पाठक, रामानुज तिवारी, रीता सिंह

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रामानुज तिवारी, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।

2. विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- जालौन, जिला- जालौन (स्थान- उरई) में पंजीकृत केस अपराध संख्या 311/2023 (धारा 380, 411 भारतीय दंड संहिता) से उत्पन्न सत्र विचारण संख्या 85/2023 में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक एफ.आई.आर. में नामजद नहीं था। तत्पश्चात, 2,000/- रुपये और एक देसी तमंचे की बरामदगी के आधार पर आवेदक को झूठा फंसाया गया है, जबकि एफ.आई.आर. में उल्लिखित घटना से आवेदक को जोड़ने वाली अन्य कोई आपत्तिजनक सामग्री मौजूद नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि सह-अभियुक्त जितेंद्र राजपूत उर्फ बोरा और चांद बाबू को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा पहले ही

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 17575/2024 और 9023/2026 में पारित आदेश दिनांक 14.05.2024 और 17.03.2026 के माध्यम से जमानत पर रिहा किया जा चुका है। अतः, आवेदक भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने का हकदार है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ने संलग्न शपथ पत्र में तीन मामलों के आपराधिक इतिहास को स्पष्ट किया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 07.10.2023 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने के साथ-साथ **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह विचार है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक- **शमशाद** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से विचारण/विवेचना में सहयोग करेगा।
 - iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध करने में शामिल नहीं होगा।
 - iv. आवेदक द्वारा निष्पादित बंध पत्र की शर्तों के अनुसार वह उपस्थित रहेगा।
7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
8. बंध पत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर इस वचन पत्र के साथ रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।
10. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, संदर्भ : स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, (2024) 10 एससी 685 जो 31.01.2023 को निर्णीत हुआ,** में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजी जाए।

20 मार्च, 2026

एससी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

Translated Version. Not For Legal Use.

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।